



CHETANA
International Journal of Education (CIJE)

Peer Reviewed/Refereed Journal
ISSN : 2455-8279 (E)/2231-3613 (P)

Impact Factor
SJIF 2025-8.445



Prof. A.P. Sharma
Founder Editor, CIJE
(25.12.1932 - 09.01.2019)

बूँदी जिले के कृषि परिदृश्य में चावल उत्पादन की प्रवृत्तियाँ: भौगोलिक विश्लेषण एवं चुनौतियाँ

आरती दाधीच

शोधार्थी

डॉ. मोहम्मद हनीफ़ खान

शोध निर्देशक

कॅरियर पाइंट यूनिवर्सिटी अलनिया, कोटा

Email-aratidadhich22@gmail.com, Mobile-7357268510

First draft received: 15.11.2025, Reviewed: 18.11.2025

Final proof received: 21.11.2025, Accepted: 28.11.2025

सारांश

बूँदी जिले में उष्णकटिबंधीय अर्ध-शुष्क जलवायु पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 725 मिमी है, जो मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान होती है। चावल जैसी जल-प्रमुख फसल के लिए यह वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसून की अस्थिरता उत्पादन को सीधे प्रभावित करती है।

बूँदी में मुख्य रूप से दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं—काली कपास (ब्लैक कॉटन) मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। काली मिट्टी जल को अधिक समय तक रोककर रखने की क्षमता रखती है, जो चावल उत्पादन के लिए अनुकूल है। वहीं जिले में मेज नदी, कनोठा नदी, तथा चम्बल नदी की सहायक नहरें प्रमुख सिंचाई स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त तलावों और बंधों की परंपरागत प्रणाली भी कृषि सिंचाई में सहायक है।

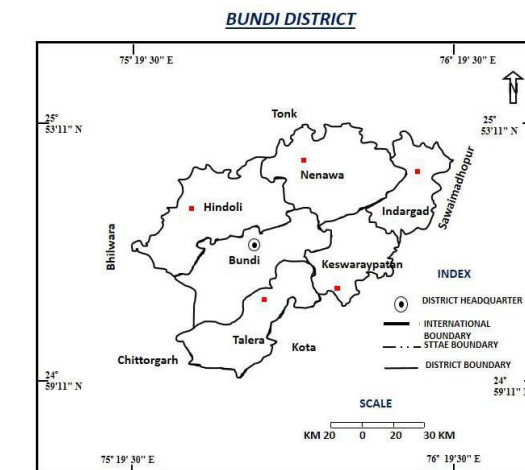
मुख्य शब्द: काली कपास (ब्लैक कॉटन) मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी आदि.

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ चावल (*Oryza sativa*) प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। राजस्थान में सामान्यतः शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण चावल उत्पादन सीमित क्षेत्रों में ही संभव है। किंतु कोटा सम्भाग के बूँदी जिले में चावल उत्पादन वर्षों से एक विशिष्ट कृषि गतिविधि के रूप में विकसित हुआ है। जिले में चावल का उत्पादन मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में होता है, जहाँ नदियों, नहरों और तालाबों के माध्यम से पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जाता है। यह लेख बूँदी जिले में चावल उत्पादन की प्रवृत्तियों का भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है तथा इसके सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर प्रकाश डालता है।

बूँदी जिले का भौगोलिक परिदृश्य

बूँदी जिला राजस्थान के दक्षिण-पूर्वी भाग में स्थित है। यह कोटा सम्भाग का एक महत्वपूर्ण जिला है, जो उत्तरी अक्षांश 25°18' से 25°53' और पूर्वी देशांतर 75°19' से 76°19' के बीच स्थित है। जिले की औसत ऊँचाई लगभग 268-302 मीटर है। यहाँ का स्थलरूप अरावली पर्वत श्रृंखला की संरचनाओं तथा पठारी भू-आकृति से निर्मित है।



बूँदी जिले में उष्णकटिबंधीय अर्ध-शुष्क जलवायु पाई जाती है। औसत वार्षिक वर्षा लगभग 725 मिमी है, जो मुख्यतः दक्षिण-पश्चिमी मानसून के दौरान होती है। चावल जैसी जल-प्रमुख फसल के लिए यह वर्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसून की अस्थिरता उत्पादन को सीधे प्रभावित करती है।

बूंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं—काली कपास (ब्लैक कॉटन) मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। काली मिट्टी जल को अधिक समय तक रोककर रखने की क्षमता रखती है, जो चावल उत्पादन के लिए अनुकूल है। वहीं जिले में मेज नदी, कनोठा नदी, तथा चम्बल नदी की सहायक नहरें प्रमुख सिंचाई स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त तलावों और बंधों की परंपरागत प्रणाली भी कृषि सिंचाई में सहायक है।

बूंदी जिले में चावल उत्पादन का ऐतिहासिक विकास

राजस्थान में चावल सामान्यतः सीमित क्षेत्रों में ही उगाया जाता रहा है। बूंदी जिले में चावल उत्पादन का विस्तार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बढ़ा, जब नहर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ। कोटा बैराज प्रणाली ने जिले में धान की खेती को तकनीकी आधार प्रदान किया। आधुनिक उच्च-उपज किस्मों (HYVs) और रासायनिक उर्वरकों की उपलब्धता ने भी उत्पादन में वृद्धि की।

21वीं सदी में चावल उत्पादन की प्रवृत्तियों में कई उल्लेखनीय परिवर्तन सामने आए हैं। आधुनिक कृषि तकनीकों का बढ़ता उपयोग, उन्नत एवं संकर बीजों की लोकप्रियता, बाजार-केन्द्रित कृषि पद्धतियाँ, तथा कृषि जल प्रबंधन में सुधार इन परिवर्तनों के प्रमुख कारक हैं। बूंदी जिले में भी 2019 से अब तक इन प्रवृत्तियों ने चावल उत्पादन की दिशा और स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं।

क्षेत्रीय वितरण और उत्पादन क्षमता

बूंदी जिले में चावल की खेती मुख्यतः उन्हीं क्षेत्रों में केंद्रित है जहाँ नहरों, कुँओं तथा अन्य सिंचाई स्रोतों से पर्याप्त जल उपलब्ध होता है। नैनवां, लाखेरी, हिंडोली और केशवरायपाटन जैसे क्षेत्रों में भू-धार, मिट्टी की जलधारण क्षमता और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के कारण धान उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक देखा जाता है। वर्ष 2019 के बाद चावल उत्पादन का क्षेत्र लगभग 82,000 हेक्टेयर तक पहुंचा, जो जिले में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसके साथ-साथ वर्षों में जिले से चावल का निर्यात भी बढ़कर महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि बन गया, और बूंदी द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 1,400 करोड़ रुपये मूल्य का चावल बाहर भेजा जाने लगा।

खेती के तरीकों में बदलाव

पिछले दशक में खेती की तकनीकों में कई परिवर्तन हुए हैं। रोपा पद्धति (transplanting) का चलन तेज़ी से बढ़ा है, जिससे पौधों की जीवितता और उत्पादकता में सुधार हुआ है। यांत्रिकीकरण—जैसे ट्रैक्टर, रोटोवेटर और पावर टिलर—का उपयोग बढ़ा है, जिससे श्रम पर निर्भरता कम हुई है। साथ ही धान की उन्नत और संकर किस्मों का व्यापक उपयोग उत्पादन बढ़ाने में सहायक रहा है। हालांकि, 2019 के बाद बीज, उर्वरक और तकनीकी साधनों की लागत बढ़ी है, जिससे उत्पादन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। जल संरक्षण तकनीकों जैसे श्रेणी सिंचाई और खेत-तलाब प्रणाली का उपयोग भी बढ़ा है, परंतु इन तकनीकों को अपनाने में छोटे किसानों को आर्थिक चुनौतियाँ झेलनी पड़ती हैं।

सिंचाई पर निर्भरता

बूंदी जिले में धान की खेती लगभग पूरी तरह सिंचित कृषि पर आधारित है। प्राकृतिक वर्षा केवल आरंभिक विकास चरण में सहायक होती है, परंतु संपूर्ण फसल चक्र के लिए नहर और कुँओं की जल उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। हाल के वर्षों में

नहरों में अनियमित जल आपूर्ति, जल वितरण की असमानता तथा सिंचाई लागत में वृद्धि जैसे कारकों ने चावल उत्पादन को प्रभावित किया है। कई क्षेत्रों में जल संकट के कारण किसान धान के स्थान पर कम जल-आवश्यकता वाली फसलों की ओर झुकते भी देखे गए हैं।

मशीनीकरण का प्रभाव

2019 के बाद से जिले में मशीनीकरण का विस्तार हुआ है। ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर और अन्य उपकरणों के उपयोग से उत्पादन क्षमता बढ़ी है और कटाई-थ्रेसिंग में समय और श्रम की बचत हुई है। हालांकि, यह सुविधा बड़े और मध्यम किसानों में अधिक दिखाई देती है, जबकि छोटे किसान अभी भी पारंपरिक उपकरणों और श्रम पर निर्भर हैं। मशीनीकरण की बढ़ती गति ने उत्पादन को तो बढ़ाया है, लेकिन इसकी लागत भी किसानों के लिए एक चुनौती बनी हुई है।

आर्थिक और बाज़ार-संबंधी चुनौतियाँ

हाल के वर्षों में चावल के बाजार भाव में गिरावट से किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। उत्पादन बढ़ने के बावजूद मंडी भाव अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाए, जिससे आय में कमी दर्ज हुई है। निर्यात बाजारों में उतार-चढ़ाव, विशेषकर मध्य-पूर्व देशों में मांग कम होने से, बूंदी के चावल उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उत्पादन लागत बढ़ने और MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर अनिश्चितता ने किसानों की आर्थिक स्थिति को और कठिन बनाया है। मजदूरी लागत में वृद्धि और स्थानीय-बाहरी श्रमिकों की उपलब्धता में बदलाव से रोपाई और कटाई के कार्यों पर भी प्रभाव देखा गया।

बूंदी में चावल उत्पादन की सामाजिक-आर्थिक प्रवृत्तियाँ

कृषि मजदूरी और श्रमिकों की उपलब्धता

बूंदी जिले में धान की खेती मुख्यतः पारंपरिक तकनीकों, रोपाई-आधारित विधियों और मैनुअल कटाई पर निर्भर करती है, जिसके कारण यह फसल अत्यधिक श्रम-सघन मानी जाती है। रोपाई के मौसम में बड़ी संख्या में अस्थायी या प्रवासी मजदूरों की आवश्यकता होती है। परंतु हाल के वर्षों में मजदूरों का पलायन अन्य रोजगार अवसरों की ओर बढ़ा है—जैसे निर्माण कार्य, मनरेगा, या शहरी क्षेत्रों में मजदूरी। इससे स्थानीय स्तर पर मजदूरों की उपलब्धता कम हुई है।

मजदूरों की कमी से मजदूरी दरों में तेज़ वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप धान की खेती की लागत काफी बढ़ गई है। छोटे और सीमान्त किसानों पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है क्योंकि उनकी लागत वहन क्षमता सीमित होती है। बढ़ती मजदूरी के साथ मशीनरी का प्रयोग बढ़ा है, लेकिन धान की रोपाई में पूर्ण मशीनीकरण अभी व्यापक नहीं है—या तो लागत अधिक है, या खेतों की संरचना अनुकूल नहीं है। परिणामस्वरूप, धान की खेती छोटे किसानों के लिए कम आकर्षक होती जा रही है, और कई किसान धीरे-धीरे कम जल-आवश्यक या कम श्रम-गहन फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।

बाजार और मूल्य प्रसार (Market Dynamics and Price Spread)

बूंदी जिले में चावल की खरीद का प्रमुख माध्यम सरकारी एजेंसियाँ—जैसे खाद्य निगम (FCI) या राज्य खाद्य आपूर्ति निगम—तथा स्थानीय निजी व्यापारी हैं। सैद्धांतिक रूप से किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान बेचने की सुविधा

उपलब्ध है, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर कई किसानों को विभिन्न कारणों से MSP का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता।

कई बार खरीद केंद्रों की दूरी, सीमित खरीद क्षमता, गुणवत्ता-मानकों की कठोरता और लंबी प्रतीक्षा अवधि के कारण किसान अपनी उपज निजी व्यापारियों को बेचने को मजबूर होते हैं। निजी मंडियों में उन्हें अक्सर MSP से कम मूल्य मिलता है, जिससे किसान - बाजार मूल्य प्रसार (price spread) बढ़ जाता है। यह अंतर व्यापारियों के लाभ को बढ़ाता है, लेकिन किसान का वास्तविक लाभ घटाता है। इसके अतिरिक्त, भंडारण सुविधाओं की कमी भी एक बड़ी समस्या है। आधुनिक गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, या वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं के अभाव में किसान कटाई के तुरंत बाद अपनी फसल को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। यदि बाजार में अधिशेष उपज हो, तो कीमतें गिर जाती हैं और किसानों की आय प्रभावित होती है। इस कारण किसान बाजार की अस्थिरता के प्रति अत्यंत संवेदनशील बने रहते हैं।

लागत और लाभ का अनुपात (Cost-Benefit Ratio)

धान उत्पादन में उपयोग होने वाले उर्वरक, कीटनाशक, डीज़ल, बिजली, सिंचाई, और मशीनरी किराए की लागत पिछले वर्षों में लगातार बढ़ी है। इनपुट लागत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत (Cost of Cultivation) में उल्लेखनीय वृद्धि होती जा रही है। यद्यपि वैज्ञानिक कृषि विधियाँ और उच्च उपज किस्में (HYVs) उत्पादन में वृद्धि करती हैं, लेकिन इनके साथ उर्वरक, सिंचाई और कीटनाशकों की अधिक आवश्यकता रहती है, जिससे लागत और बढ़ जाती है।

इसके अलावा, डीज़ल कीमतों में उतार-चढ़ाव सीधे खेत संचालन, पंपिंग सेट, ट्रैक्टर उपयोग, एवं परिवहन लागत पर प्रभाव डालते हैं। बढ़ी हुई लागत के मुकाबले बिक्री मूल्य में समुचित वृद्धि नहीं हो पाने से किसानों की लाभप्रदता (profitability) घट जाती है। कुछ किसान लाभ-हानि संतुलन (break-even point) पर ही खेती करने को मजबूर हैं, जबकि कई किसान धीरे-धीरे धान उत्पादन से हटकर बाजरा, गेहूँ, सरसों या सब्जियों जैसी कम लागत और कम जोखिम वाली फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।

यह स्थिति क्षेत्रीय खाद्यान्न सुरक्षा (food security) को भी प्रभावित कर सकती है, क्योंकि धान स्थानीय आहार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) का महत्वपूर्ण घटक है। किसानों की आय में कमी का सामाजिक प्रभाव भी दिखाई देता है—गृहस्थी की क्रय शक्ति में कमी, कृषि निवेश में गिरावट, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मंदी।

बूंदी जिले में चावल उत्पादन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

जल संकट और सिंचाई पर दबाव

चावल जल-प्रधान फसल है, जिसके लिए 1200-1800 मिमी पानी की आवश्यकता होती है। बूंदी जैसे अर्ध-शुष्क क्षेत्र में नहर जल पर अत्यधिक निर्भरता उत्पादन के लिए बड़ी चुनौती है। जल उपलब्धता में वर्ष दर वर्ष गिरावट, बढ़ती जनसंख्या, तथा भूजल दोहन इस समस्या को बढ़ाते हैं।

मिट्टी की उर्वरता में गिरावट

लगातार धान की खेती से मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है, विशेषकर नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी। अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की संरचना प्रभावित हो रही है।

जलवायु परिवर्तन

बरसात का अनियमित होना, तापमान में वृद्धि तथा चरम मौसमीय परिस्थितियाँ धान उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। मॉनसून में देरी होने पर बोवाई का समय प्रभावित होता है, जिससे उत्पादकता घटती है।

रोग और कीट समस्याएँ

धान की फसल में झुलसा रोग, ब्लास्ट, भूरे धब्बे, तना छेदक आदि रोगों के कारण उत्पादन में गिरावट होती है। किसानों के पास रोग प्रबंधन की जानकारी सीमित है।

बाज़ार एवं भंडारण सुविधाओं का अभाव

उत्पादन के बाद कृषि विपणन की चुनौतियाँ—जैसे उचित मूल्य न मिलना, परिवहन समस्या, गोदामों की कमी—किसानों को आर्थिक रूप से कमजोर बनाती हैं।

तकनीकी ज्ञान का अभाव

छोटे और सीमांत किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, कुशल जल प्रबंधन, और रोग नियंत्रण उपायों से पर्याप्त रूप से परिचित नहीं हैं। इससे उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है।

सरकारी योजनाएँ और सुधार की संभावनाएँ

कृषि विभाग एवं अनुसंधान केंद्रों की भूमिका

बूंदी जिले में कृषि विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र (KVK-Bundi) किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों से जोड़ने में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। जिले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा धान की उच्च उपज देने वाली किस्मों—जैसे राज-4237, आरएच-1531 तथा कुछ स्थानीय अनुकूल संकर किस्मों—के प्रदर्शन प्लॉट स्थापित किए गए हैं, जिनसे किसानों ने 15-20% तक अधिक उत्पादन प्राप्त किया। KVK-Bundi ने 2019 के बाद से कई Front Line Demonstrations (FLD) आयोजित किए, जिनमें रोग-प्रतिरोधी किस्मों और वैज्ञानिक उर्वरक प्रबंधन को विस्तार से समझाया गया। इसके अतिरिक्त, कृषि विभाग द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, कीट-नियंत्रण सलाह तथा मोबाइल-आधारित कृषि सूचना सेवाएँ किसानों को आधुनिक तकनीक और मौसम आधारित खेती अपनाने में सहायक रही हैं।

नहरों और जल-संरक्षण संरचनाओं का विकास

बूंदी में धान उत्पादन के लिए नहर प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है—विशेषकर भागोल बांध, नैनवां नहर, लाखेरी फीडर, और रामगढ़ बांध कमांड क्षेत्र प्रमुख सिंचाई स्रोत हैं। जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए जिले में 2020 के बाद जल-जीवन-मिशन, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (MJSA) तथा मनरेगा के माध्यम से सैकड़ों छोटे चेक-डैम, खेत-तालाब और स्टॉप डैम निर्मित किए गए। इन संरचनाओं के कारण नैनवां, हिंडोली और केशवरायपाटन के कई गांवों—जैसे संजेली, चमराज का खेड़ा, लाक्षाग्रहम—में धान की खेती का रकबा बढ़ा है। खेत-तालाबों ने किसानों को अतिरिक्त सिंचाई का विकल्प दिया है, जिससे धान की रोपाई समय पर हो पाती है और सूखे वर्षों में भी जोखिम कम होता है।

किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

KVK-Bundi नियमित रूप से किसानों के लिए प्रशिक्षण, फील्ड डेमो और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है। 2019 के बाद जिले में विशेष रूप से निम्न विषयों पर प्रशिक्षण दिए गए:

- Direct Seeded Rice (DSR) तकनीक — कम पानी और कम श्रम में धान उत्पादन हेतु। हिंडोली और नैनवां के किसानों ने DSR अपनाकर 20-25% पानी की बचत दर्ज की।
- इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट और पेस्ट मैनेजमेंट — जिससे उत्पादन खर्च में कमी आई।
- स्मार्ट इरीगेशन (माइक्रो-सिंचाई, रेनगन सिस्टम) का प्रदर्शन।
- फसल बीमा और MSP जागरूकता शिविर — किसानों के अधिकार और बाजार जानकारी के लिए।
- Central Ground Water Board (CGWB), राजस्थान। (2022). जल संसाधन एवं भूविज्ञान रिपोर्ट – बूंदी जिला. CGWB रिपोर्ट।

2022-2024 के दौरान KVK ने “धान उन्नयन कार्यक्रम” के अंतर्गत 250 से अधिक किसानों के प्लॉट पर प्रदर्शन किया, जिसमें उत्पादन वृद्धि और श्रम-लागत में कमी स्पष्ट देखी गई।

बाजार सुधार और MSP का प्रभावी क्रियान्वयन

बूंदी मंडी क्षेत्र हाड़ौती का प्रमुख धान व्यापार केंद्र है, जहाँ लाखेरी, नैनवां और हिंडोली के किसान बड़े पैमाने पर चावल बेचते हैं। बाजार में पिछले कुछ वर्षों में मूल्य में उतार-चढ़ाव से किसानों को समस्या हुई, इसलिए सरकार द्वारा MSP पर खरीद को बढ़ावा दिया गया।

हाल ही में बूंदी के सहकारी विपणन संघ (MARKFED) द्वारा किसानों से अधिक मात्रा में धान की सरकारी खरीद की गई, जिससे छोटे किसानों को लाभ मिला।

इसके अलावा, जिले में किसान उत्पादक संगठन (FPO) जैसे—

- लाखेरी धान उत्पादक ग्रुप,
- नैनवां कृषि उत्पादक कंपनी, किसानों को सामूहिक बिक्री, बेहतर मूल्य वार्ता और इनपुट खरीद में मदद कर रहे हैं। इन FPO के माध्यम से कई किसानों को बिचौलियों पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम हुई है, जिससे उन्हें अधिक शुद्ध लाभ प्राप्त हो रहा है।

बूंदी जिले में चावल उत्पादन भौगोलिक रूप से विशिष्ट परिस्थितियों पर आधारित है, जहाँ जल संसाधन, मिट्टी की संरचना, स्थलाकृति और जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में जिले ने तकनीकी सुधारों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि दर्ज की है, परंतु जल संकट, जलवायु परिवर्तन, मिट्टी की गुणवत्ता, मौसमी अनिश्चितता और बाजार चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

भविष्य में जल संरक्षण तकनीकों, उन्नत कृषि पद्धतियों, रोग-प्रतिरोधी किस्मों, और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से बूंदी जिले में चावल उत्पादन को स्थिर और टिकाऊ बनाया जा सकता है। कृषि का यह क्षेत्र न केवल जिले की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की क्षमता रखता है बल्कि खाद्यान्न सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।

संदर्भ

- Gautam, B. (n.d.). Factors responsible for the development of rice industry in district Bundi. Social Research Foundation.
- IOSR Journal of Humanities and Social Science. (2022). Geographical conditions and crop production in Bundi district (Vol. 27, Issue 8, Ser. 11, pp. 37-44). IOSR-JHSS.